

छत्तीसगढ़ के बारनवापारा में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की संभावनाएँ: एक सैद्धांतिक विश्लेषण

निधि मिश्रा

वाणिज्य संकाय

सेठ आर सी एस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्गा, छत्तीसगढ़

सारांश

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वन उपज की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषकर आदिवासी और वन सीमावर्ती क्षेत्रों में। हालांकि वन उपज का संग्रहण मौसमी रोजगार प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश उत्पाद कच्चे रूप में न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ बेचे जाते हैं, जिससे संग्रहणकर्ताओं की आय कम होती है। प्रस्तुत सैद्धांतिक अध्ययन छत्तीसगढ़ के बारनवापारा वन क्षेत्र में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। बारनवापारा में समृद्ध जैव विविधता है, यह वन गांवों के निकट है और रायपुर और महासमुंद जैसे शहरी बाजारों से सड़क संपर्क स्थापित है। यह शोधपत्र प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार मांग, आजीविका लाभ और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करता है। अध्ययन से पता चलता है कि एक प्रसंस्करण केंद्र ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, रोजगार सृजित कर सकता है, मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को कम कर सकता है और आदिवासी समुदायों को औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करते हुए सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकता है।

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ को व्यापक रूप से वन आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, जहाँ ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा हिस्सा गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्रहण पर निर्भर है। इन उत्पादों में महुआ के फूल और बीज, इमली, आंवला, हर्षा, बहेड़ा, चिरौंजी, शहद और लाख शामिल हैं। हालांकि उत्पादन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन संग्रहणकर्ताओं को मिलने वाला आर्थिक लाभ सीमित रहता है क्योंकि अधिकांश उत्पाद कच्चे रूप में ही गाँव से बाहर भेजे जाते हैं। स्थानीय प्रसंस्करण अवसररचना के अभाव के कारण संग्रहणकर्ताओं को कटाई के तुरंत बाद ही बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

बारनवापारा एक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान है क्योंकि यह वन समृद्ध क्षेत्र में स्थित है और कई वन-निर्भर गाँवों से घिरा हुआ है। साथ ही, यह शहरी उपभोग केंद्रों के अपेक्षाकृत निकट है। संसाधनों की उपलब्धता और बाजार तक पहुँच का यह संयोजन वन आधारित कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

प्रसंस्करण केंद्र की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि वन उत्पादों की विपणन क्षमता केवल खरीद पर ही नहीं बल्कि मूल्यवर्धन पर भी निर्भर करती है। प्रसंस्करण से उत्पादों की शोल्फ लाइफ बढ़ती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होती है और संग्रहण गतिविधियों के अलावा रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।

बारनवापारा क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता

बारनवापारा वन क्षेत्र में मिश्रित पर्णपाती प्रजातियों सहित विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। खाद्य, औषधीय और औद्योगिक वन उत्पादों की मौसमी उपलब्धता अधिक है। महुआ के पेड़ आसपास के गाँवों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और फूल और बीज दोनों उत्पन्न करते हैं। इमली के पेड़ वन सीमाओं और ग्राम भूमि में आम हैं। आंवला और हर्षा वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जबकि लाख के पेड़ भी आसपास के क्षेत्रों में मौजूद हैं।

विभिन्न उत्पादों का निरंतर मौसमी चक्र पूरे वर्ष प्रसंस्करण की क्षमता सुनिश्चित करता है। महुआ वसंत ऋतु में, इमली ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में, औषधीय पौधे मानसून और शीत ऋतु में और लाख विभिन्न समयों पर उपलब्ध होते हैं, जो कि पौधों के अंकुरण चक्र पर निर्भर करता है। इस भिन्न-भिन्न उपलब्धता के कारण प्रसंस्करण केंद्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य है क्योंकि मशीनें और श्रमिक पूरे वर्ष सक्रिय रह सकते हैं।

आर्थिक अवसर

सबसे महत्वपूर्ण अवसर मूल्यवर्धन है। कच्चे महुआ के फूल आमतौर पर कम दामों पर बिकते हैं, लेकिन प्रसंस्करण से खाद्य पाउडर, मिठाइयाँ, स्वास्थ्य पूरक और बेकरी सामग्री तैयार की जा सकती है। इमली को गूदे के ब्लॉक, सांद्रण और पकाने के लिए तैयार मसालों में संसाधित किया जा सकता है। आंवला को कैंडी, पाउडर, जूस और हर्बल फॉर्मूलेशन में परिवर्तित किया जा सकता है। हर्षा और बहेरा हर्बल दवा उद्योग को आपूर्ति कर सकते हैं। प्रसंस्करण से कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। केवल संग्रहण मजदूरी कमाने के बजाय, स्थानीय परिवार सफाई, ग्रेडिंग, सुखाने, पैकेजिंग और परिवहन कार्यों में भाग ले सकते हैं। इससे आय सृजन मौसमी श्रम से अर्ध-औद्योगिक रोजगार की ओर स्थानांतरित होता है। एक प्रसंस्करण केंद्र पैकेजिंग सामग्री आपूर्ति, परिवहन सेवाएं, स्थानीय खुदरा दुकानों और खाद्य उद्यमों जैसी अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधियों को भी जन्म देगा। इसका गुणक प्रभाव आसपास के गांवों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।

बाजार संपर्क के लाभ

बारनवापारा प्रमुख शहरी बाजारों, विशेषकर रायपुर के निकट स्थित है। इस निकटता से परिवहन लागत कम होती है और शहरी उपभोक्ताओं को ताजे और प्रसंस्कृत उत्पादों की आपूर्ति आसान हो जाती है। जैविक खाद्य पदार्थों, हर्बल दवाओं और प्राकृतिक स्वास्थ्य उत्पादों की बढ़ती शहरी मांग एक मजबूत बाजार आधार प्रदान करती है। प्रसंस्करण और ब्रांडिंग से वन उत्पादों को सुपरमार्केट, संस्थागत आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऑनलाइन खुदरा प्लेटफार्मों तक पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक वन मूल पर जोर देने वाली क्षेत्रीय पहचान के तहत पैकेजिंग प्रीमियम उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकती है। इससे बाजार व्यापारी-नियंत्रित खरीद से उपभोक्ता-संचालित मांग की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।

आजीविका और सामाजिक प्रभाव

प्रसंस्करण केंद्र में आदिवासी कल्याण में सुधार लाने की अपार क्षमता है। वर्तमान में, फसल कटाई के तुरंत बाद संग्राहक उत्पाद बेच देते हैं, क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। एक स्थानीय प्रसंस्करण इकाई उचित मूल्य पर सीधे उत्पाद खरीद सकती है और तुरंत भुगतान कर सकती है।

रोजगार सृजन एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ है। वन उत्पादों की प्राथमिक संग्राहक महिलाएं छंटाई, सुखाने और पैकेजिंग में नियमित कार्य प्राप्त कर सकती हैं। युवाओं को मशीनरी संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण और रसद का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे शहरों की ओर पलायन कम होगा और स्थानीय आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।

स्वयं सहायता समूहों को प्रसंस्करण कार्यों में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित होगा। सामूहिक भागीदारी से सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है और बैंक से जुड़े लेनदेन के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरण पर प्रभाव

एक सुव्यवस्थित प्रसंस्करण केंद्र वन संरक्षण में सहायक हो सकता है। जब समुदायों को वन उत्पादों से अधिक आय प्राप्त होती है, तो उन्हें वृक्षों को काटने के बजाय उनकी रक्षा करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। पुनर्जनन कार्यक्रमों को खरीद समझौतों से जोड़ा जा सकता है, जिससे आंवला, इमली और लाख जैसे वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रसंस्करण से अपव्यय भी कम होता है। वर्तमान में, संग्रहण का एक बड़ा हिस्सा खराब भंडारण के कारण नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक सुखाने और संरक्षण विधियाँ वन संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। हालांकि, स्थिरता के लिए विनियमित कटाई आवश्यक है। प्रसंस्करण विकास के साथ-साथ गैर-विनाशकारी संग्रहण विधियों और नियंत्रित कटाई चक्रों में प्रशिक्षण भी अनिवार्य है।

संस्थागत एवं नीतिगत सहयोग

आदिवासी आजीविका, ग्रामीण स्वरोजगार और वन उत्पाद खरीद से संबंधित सरकारी योजनाएँ इस केंद्र की स्थापना में सहायक हो सकती हैं। सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह खरीद केंद्र संचालित कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय और वन अनुसंधान संस्थान गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीण विकास बैंकों और आजीविका मिशनों के माध्यम से वित्तीय सहायता मशीनरी, गोदामों और शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना में सहायक हो

सकती है। पोषण योजनाओं जैसे सार्वजनिक खरीद कार्यक्रम प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए सुनिश्चित खरीदार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

चुनौतियाँ और जोखिम कारक

अपनी क्षमता के बावजूद, कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित आपूर्ति प्रसंस्करण क्षमता के उपयोग को प्रभावित कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान की कमी से उत्पाद की गुणवत्ता शुरू में सीमित हो सकती है। स्थापित हर्बल ब्रांडों से बाजार प्रतिस्पर्धा भी कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है। एक अन्य जोखिम है खरीद मूल्य में तीव्र वृद्धि होने पर अत्यधिक कटाई। इसलिए, प्रसंस्करण विस्तार को टिकाऊ कटाई नियमों और वृक्षारोपण पहलों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए बिजली की विश्वसनीयता, भंडारण सुविधाओं और परिवहन संपर्क जैसी अवसंरचना को मजबूत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बारनवापारा में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना से महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अवसर प्राप्त होंगे। इस क्षेत्र में पर्याप्त कच्चा माल, श्रम आपूर्ति और बाजार तक पहुंच उपलब्ध है। प्रसंस्करण से वन उपज को कम मूल्य वाली मौसमी वस्तु से उच्च मूल्य वाले व्यावसायिक उत्पाद में बदला जा सकता है। ऐसा केंद्र आय में वृद्धि करेगा, रोजगार सृजित करेगा, महिलाओं को सशक्त बनाएगा और प्रवासन को कम करेगा, साथ ही सतत वन संरक्षण को बढ़ावा देगा। इस पहल की सफलता खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और संरक्षण को एक ही ढांचे में एकीकृत करने पर निर्भर करती है। यदि इसे सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग के साथ लागू किया जाता है, तो प्रसंस्करण केंद्र वन संसाधनों पर आधारित ग्रामीण औद्योगीकरण का एक मॉडल बन सकता है और छत्तीसगढ़ में दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा में योगदान दे सकता है।

REFERENCES

1. Mahapatra, A. K. and Tewari, D. D. (2005). Importance of non timber forest products in rural livelihood security: Evidence from India. *Forest Policy and Economics*, 7(3), 447 to 458.
2. Government of India, Ministry of Tribal Affairs. (2013). *Minimum Support Price Scheme for Minor Forest Produce: Operational Guidelines*. New Delhi.
3. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development). (2017). *Value Chain Financing and Promotion of Minor Forest Produce Based Enterprises in Central India*. Mumbai.
4. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.). (2016). *Van Dhan Vikas Kendra: Guidelines for Value Addition, Processing and Marketing of Minor Forest Produce*. New Delhi.